सिडबी

पुनर्वित्त - योजना संबंधी विशिष्ट मानदंड

Refinance – Scheme Specific Norms

(कृपया इसे पुनर्वित्त योजना के एक-समान मानदंडों के साथ पढ़ें)

(Please read together with refinance common norms)

1. सूक्ष्म और लघु उद्यम पुनर्वित्त (एमएसईआर) योजना

Micro and Small Enterprises Refinance (MSER) Scheme

क्र.सं. Sl. No.	विवरण / Particulars	
1	योजना Scheme	सूक्ष्म और लघु उद्यम पुनर्वित्त (एमएसईआर) योजना Micro and Small Enterprises Refinance (MSER) Scheme
2	योजना का उद्देश्य Objective of scheme	बैंकों को पुनर्वित्त के माध्यम से एमएसई क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुविधाजनक बनाकर सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को सहायता प्रदान करना। To support Micro and Small Enterprises (MSEs) by facilitating flow of credit to the MSE sector by way of refinance of banks' lending to MSEs.
3	ब्याज दर / वाणिज्यिक शर्तें Rate of interest / Commercial Terms	❖ ब्याज दर बाजार द्वारा निर्धारित होती है । बाजार की स्थितियों के आधार पर ब्याज दर और अन्य वाणिज्यिक शर्तों का निर्धारण किया जाएगा। ❖ सामान्य करार के अनुसार मूलधन, ब्याज और अन्य धनराशि की किस्तों के भुगतान में चूक के लिए दंडात्मक प्रभारों के रूप में लागू उधार दर से अधिक प्रयोज्य करों के साथ 2% वार्षिक का प्रभार लगाया जाएगा। ❖ Rate of interest is market determined. The rate of interest and other commercial terms would be negotiated, depending on market conditions. ❖ A charge of 2% p.a., along with applicable taxes over and above the applicable lending rate, will be levied, by way of penal charges, for defaults in payment of installments of principal, interest and other monies as per General Agreement.
4	पुनर्वित्त की अवधि Period of refinance	❖ 5 साल तक / Up to 5 years.

5	मूलधन/ब्याज के भुगतान के लिए आवधिकता Periodicity for payment of Principal / Interest	❖ मूलधन चुकौती: बाजार की स्थितियों और बैंक की आवश्यकताओं के आधार पर प्रत्येक बैंक के साथ संबंधित अवधि सहित, चुकौती की शर्तें बातचीत की जाती है। ❖ ब्याज भुगतान: मासिक। तथापि, यदि चुकौती की नियत तारीख एनआई अधिनियम के तहत शनिवार/रविवार या अवकाश के दिन हो, तो नियत तारीख पूर्ववर्ती कार्यदिवस को मानी जाएगी। ❖ Principal repayment: The repayment terms, including tenor, are negotiated with each bank, depending upon market conditions and requirements of the bank. ❖ Interest payment: Monthly. However, if the due date of repayment falls on Saturday/ Sunday or Holiday under N.I. Act, the due date would shift to preceding working day.

2. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए पुनर्वित्त योजना (आरएमएसई)
Refinance Scheme for Micro and Small Enterprises (RMSE)

क्र.सं. Sl. No.	विवरण / Particulars	
1	योजना / Scheme	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए पुनर्वित्त योजना (आरएमएसई) के दो घटक हैं – 1) अभिज्ञात ऋण की कमी वाले जिलों में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए पुनर्वित्त योजना (आरएमएसई-आईसीडीडी) - भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित 196 अभिज्ञात ऋण की कमी वाले जिलों (आईसीडीडी) में ऋण देने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करके क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना। 2) गैर-आईसीडीडी में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु पुनर्वित्त योजना (आरएमएसई-नियमित) - सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों को प्रोत्साहन देना। Refinance Scheme for Micro and Small Enterprises (RMSE) has two components - 1) Refinance Scheme for Micro and Small Enterprises in Identified Credit Deficient Districts (RMSE-ICDD) - To address regional disparities by encouraging banks to lend in 196 Identified

		Credit Deficient Districts (ICDDs) as notified by RBI from time to time. 2) Refinance Scheme for Micro and Small Enterprises in non-ICDDs (RMSE-Regular) - Incentivizing banks' lending to Micro-Enterprises.
2	निधि / Fund	भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) संबंधी लक्ष्यों/उप-लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी वाले बैंकों द्वारा किए गए अंशदानों में से सिडबी को एमएसई पुनर्वित्त निधि (एमआरएफ) आवंटित करता रहा है। एमआरएफ का उपयोग आरएमएसई के अंतर्गत पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए किया जाता है। Reserve Bank of India (RBI) has been allocating MSE Refinance Fund (MRF) to SIDBI out of contributions made by banks having shortfall in achievement of Priority Sector Lending (PSL) targets/sub-targets. The MRF is utilised in extending refinance under RMSE.
3	योजना का उद्देश्य Objective of scheme	बैंकों को पुनर्वित्त के माध्यम से एमएसई क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुविधाजनक बनाकर सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को सहायता प्रदान करना। To support Micro and Small Enterprises (MSEs) by facilitating flow of credit to the MSE sector at reasonable rate of interest by way of refinance banks' lending to MSEs.
4	उपयुक्त प्राथमिक ऋण देने वाले संस्थान (पीएलआई) Eligible Primary Lending Institutions (PLIs)	भारतीय रिजर्व बैंक से सिडबी द्वारा प्राप्त पीएलआई की सूची के अनुसार, नियमित घटक के अंतर्गत। As per list of PLIs received by SIDBI from RBI, under Regular Component.
5	बैंकों द्वारा अंतिम उधारकर्ताओं से ली जाने वाली अंतिम ऋण दर Final lending rate charged to end-borrowers by banks	**<u>आरएमएसई-नियमित:</u>** ❖ बाहरी बेंचमार्क "10-वर्षीय जी-सेक प्रतिफल" पर 350 बीपीएस तक। **<u>आरएमएसई-आईसीडीडी:</u>** ❖ बाहरी बेंचमार्क "10-वर्षीय जी-सेक प्रतिफल " पर 450 बीपीएस तक। *नोट:* • *तिमाही के अंतिम दिन की आय का उपयोग आगामी तिमाही के लिए पुनर्वित्त हेतु बैंक ऋणों की पात्रता पर विचार करने के लिए किया जा सकता है।* • *प्रत्येक तिमाही के लिए प्रयोज्य प्रतिफल सिडबी की वेबसाइट पर जारी की जाती है।*

		RMSE-Regular: ❖ **Up to 350 bps** over the External Benchmark "10-year G-Sec yield". **RMSE-ICDD:** ❖ **Up to 450 bps** over the External Benchmark "10-year G-Sec yield". *Note:* • *The yield as on the last day of the quarter may be used to consider the eligibility of Bank loans for refinance for the ensuing quarter.* • *The applicable yield for each quarter is hosted on SIDBI website.*
6	योग्य पुनर्वित्त सहायता Eligible refinance assistance	पिछले 12 महीनों के दौरान पीएलआई द्वारा संवितरित और आवेदन की तारीख को बकाया ऋण पुनर्वित्त के लिए कवर किए जा सकते हैं। Loans disbursed by PLIs during the previous 12 months and outstanding as on the date of application can be covered for refinance.
7	ब्याज दर Rate of interest	❖आरबीआई के मौजूदा बैंक दर और आरबीआई के अन्य लागू दिशानिर्देशों से जुड़ा हुआ है। ❖ सामान्य करार के अनुसार मूलधन, ब्याज और अन्य धनराशि की किस्तों के भुगतान में चूक के लिए दंड प्रभारों के रूप में लागू उधार दर से अधिक प्रयोज्य करों सहित 2.00% प्रति वर्ष का प्रभार लगाया जाएगा। ❖ Linked to prevailing RBI Bank Rate and other applicable RBI guidelines. ❖ A charge of 2.00% p.a., along with applicable taxes over and above the applicable lending rate, will be levied, by way of penal charges, for defaults in payment of installments of principal, interest and other monies as per the General Agreement.
8	पुनर्वित्त की अवधि Period of refinance	❖ 3 वर्ष तक या निधि की परिपक्वता, जो भी पहले हो। ❖ Upto 3 years or the maturity of the Fund, whichever is earlier.
9	मूलधन/ब्याज के भुगतान की आवधिकता	❖ मूलधन चुकौती: संबंधित अवधि के अंत में। ❖ ब्याज भुगतान: मासिक।

	Periodicity for payment of Principal / Interest	तथापि, यदि चुकौती की नियत तारीख एनआई अधिनियम के तहत शनिवार/रविवार या अवकाश के दिन हो, तो नियत तारीख पूर्ववर्ती कार्यदिवस को मानी जाएगी। ❖ Principal repayment: At the end of tenure. ❖ Interest payment: Monthly However, if the due date of repayment falls on Saturday/ Sunday or Holiday under N.I. Act, the due date would shift to preceding working day.

नोट: योजना के उपरोक्त मानदंड भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए आशोधनों और आरबीआई द्वारा आवंटित निधि की उपलब्धता के अधीन हैं।

Note: The above norms of the scheme are subject to changes made by GoI / RBI and the availability of funds allocated by RBI.

3. **निर्यात के प्रयोजन के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को पुनर्वित्त सहायता (आरएएमपीई)/**
Refinance Assistance to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) for the Purpose of Export (RAMPE).

क्र.सं. Sl. No.	विवरण / Particulars	
1	योजना / Scheme	निर्यात के उद्देश्य से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को पुनर्वित्त सहायता (आरएएमपीई)। Refinance Assistance to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) for the Purpose of Export (RAMPE).
2	योजना का उद्देश्य Objective of scheme	निर्यात के उद्देश्य हेतु ऋण-प्रवाह को सुविधाजनक बनाकर एमएसएमई को सहायता प्रदान करना। To support the MSMEs by facilitating flow of credit for the purpose of export.
3	पात्र प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाएँ (पीएलआई) Eligible Primary Lending Institutions (PLIs)	❖ अनुसूचित बैंक (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक और लघु वित्त बैंक) ❖ वित्तीय सहायता संबंधित पीएलआई के बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण प्राप्त करने की सीमा/शक्ति के भीतर होगी। ❖ Scheduled Banks (Public Sector Banks, Private Sector Banks, Foreign Banks and Small Finance Banks) ❖ The financial assistance shall be within the borrowing limit / Power approved by the Board of the respective PLI.

4	योजना का उद्देश्य / Purpose of scheme	निर्यात के उद्देश्य से एमएसएमई को पीएलआई द्वारा दिए प्रदत्त ऋणों और अग्रिमों हेतु पुनर्वित्त (अर्थात सावधि ऋण, प्री-शिपमेंट / पोस्ट-शिपमेंट ऋण-सीमाएं आदि)। Refinance of loans and advances extended by PLIs to MSMEs for the purpose of export (viz. Term Loans, Pre-shipment / Post-shipment Credit Limits etc.).
5	पात्र अंतर्निहित संपत्ति/अंतिम उधारकर्ता Eligible underlying assets / End-borrowers	भारत सरकार (जीओआई) के दिनांक 26 जून, 2020 की राजपत्र अधिसूचना एसओ 2119 (ई) में निर्दिष्ट सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की परिभाषा के अनुसार एमएसएमई के अनुपालक अंतिम उधारकर्ता। MSME end borrowers complying with the definition of Micro, Small and Medium Enterprises as per definition contained in Government of India (GoI), Gazette Notification S.O. 2119(E) dated June 26, 2020.
6	अंतिम उधारकर्ताओं की पात्र गतिविधियां Eligible activities of End borrowers	❖ एमएसएमई के अंतिम उधारकर्ताओं को निर्यात संबंधी गतिविधियों में रत होना चाहिए। ❖ बैंकों को यह प्रमाणित करना होगा कि एमएसएमई अंतिम उधारकर्ता निर्यात संबंधी गतिविधियों में रत हैं। ❖ MSME end borrowers should be involved in export related activities. ❖ Banks to certify that the MSME end borrowers are engaged in export related activities.
7	पात्र पुनर्वित्त सहायता Eligible refinance Assistance	सभी पुनर्वित्त योजनाओं के लिए सामान्य पुनर्वित्त मानदंडों के अतिरिक्त, आरएएमपीई के अंतर्गत, पुनर्वित्त सहायता भारतीय रुपए/विदेशी मुद्रा (उपलब्धता के अधीन) में होगी जो बैंकों की आवश्यकता के आधार पर उनके अंतर्निहित ऋणों और एमएसएमई के अंतिम उधारकर्ताओं को भारतीय रुपए/विदेशी मुद्रा में अग्रिमों पर निर्भर करेगी। In addition to the refinance norms common for all refinance schemes, the refinance assistance under RAMPE will be in Indian Rupees / Foreign Currency (subject to availability) depending upon the requirement of Banks against their underlying loans and advances to MSME end borrowers in Indian Rupees / Foreign Currency.
8	ब्याज दर / वाणिज्यिक शर्तें Rate of interest / Commercial Terms	❖ ब्याज की दर बाजार द्वारा निर्धारित होती है । बाजार की स्थितियों के आधार पर ब्याज और अन्य वाणिज्यिक दरों का निर्धारण किया जाएगा। ❖ सामान्य करार के अनुसार मूलधन, ब्याज और अन्य धनराशि की किस्तों के भुगतान में चूक के लिए दंडात्मक प्रभारों के रूप में लागू उधार दर से अधिक प्रयोज्य करों सहित 2% वार्षिक का प्रभार लगाया जाएगा।

		❖ The rate of interest is market determined. The rate of interest and other commercial, would be negotiated, depending on market conditions. ❖ A charge of 2% p.a., along with applicable taxes over and above the applicable lending rate, will be levied, by way of penal charges, for defaults in payment of installments of principal, interest and other monies as per General Agreement.
9	पुनर्वित्त की अवधि Period of refinance	5 साल तक /Up to 5 years.
10	मूलधन/ब्याज के भुगतान के लिए आवधिकता Periodicity for payment of Principal / Interest	❖ मूलधन चुकौती: बाजार की स्थितियों और बैंक की आवश्यकताओं के आधार पर प्रत्येक बैंक के साथ अवधि सहित चुकौती की शर्तों का निर्धारण किया जाएगा। ❖ ब्याज भुगतान: मासिक। ❖ तथापि यदि पुनर्भुगतान की नियत तारीख एनआई अधिनियम के तहत शनिवार/रविवार या अवकाश के दिन हो, तो नियत तारीख पूर्ववर्ती कार्यदिवस को मानी जाएगी। ❖ Principal repayment: The repayment terms, including tenor, are negotiated with each bank, depending upon market conditions and requirements of the bank. ❖ Interest payment: Monthly ❖ However, if the due date of repayment falls on Saturday/ Sunday or Holiday under N.I. Act, the due date would shift to preceding working day.

*****